

संक्षिप्त खबरें
बीमा सुरक्षा पर नई रिपोर्ट



नई दिल्ली। भारत में बीमा लेना अब आम तौर ही गया है लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि लोगों को सही बीमा सुरक्षा प्री रही है या नहीं। यह बात बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रॉकिंग लिमिटेड की नई 'सुखा कवच रिपोर्ट 2025' में कही गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे देश में बीमा का मतलब सिफ़र पॉलिसी लेना बनकर रह गया है, न कि सही कवरेज पाना।

61% शहरी परिवार मारते हैं कि अगर एक बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाए, तो उनकी वित्तीय हालात प्रभावित हो सकती है। कामकाजी महिलाओं में से सिर्फ़ 1 में से 5 के पास अपने नाम की जीवन बीमा पॉलिसी हैं। देश में 83% लोग बीमा के क्षेत्र में सिर्फ़ जानकारी हासिल करते हैं, उनमें से केवल 36% लोग ही बीमा खरीदते हैं।

फार्ट्यून का मानसून पैक

नई दिल्ली। फार्ट्यून सोयाबीन आयल ने मानसून के लिए सोयाबीन आयल को नए पैक में पेश किया है। कंपनी ने कहा कि 'मानसून संशेष ऐक बारिश के मौसम को स्वाद, मस्ती और कूपना से भर देता है।' इस बार पैक के जरिये ऑपरेटर इंटरेक्टिव (एआई) और आर्टिफिशियल इंटरेक्टिव (एआई) से पार्टनर एक बिल्यूम नव इंटरेक्टिव एक्सप्रियंस भी मिलेगा। यह लिमिटेड-एडिशन पाठव पैक कूपआर कोड के साथ आता है, जो उपार और एआई से पार्टनर है। फार्ट्यून ने दिल्ली, जयपुर और लखनऊ में एन-रिएटिव हार्डिंग्स भी लगाए हैं।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और एशियार्स विकास बैंक (एडीबी) ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने मध्य-वर्षीय अधिक परिदृश्य में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घेरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत कर दिया।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने मध्य-वर्षीय अधिक परिदृश्य में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घेरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है जो उपर किसिंग के 6.6 प्रतिशत के अनुमान से कम है। इसके बाद अन्य अधिकारीय शर्करा से एवं सार्वजनिक वित्त प्रमुख देवेलपर कुमार पंत ने कहा, 'प्रमुख प्रतिकूल परिस्थितियों में अमेरिका के सभी देशों पर एकत्रणा शुल्क से

नई दिल्ली। मारुति सुजुकी की सोनीपत शिथत मास्टर अनुल सरकारी आईआई में अपने नए स्थानीय प्रक्रिया शुरू कर दी है। जोआईएम सोनीपत के पहले बैच में चार ड्रेंडों में कोनेक्ट मोटर हीलैन (एएमटी), मशीनिंस, वेल्डर और फिर्टर ड्रेंड में 100 से अधिक छात्र प्रेसो ले सकेंगे। पहला सत्र शर्करा में शुरू होगा। मारुति सुजुकी ने जोआईएम सोनीपत की शास्त्राना के लिए 10 करोड़ रुपये में की धारायाँ आवंटित की हैं।

कोटक महिंद्रा का नया प्लान

नई दिल्ली। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शिथत मास्टर टर्म प्लान लांच करने की घोषणा की है। यह एक शुरू क्षमता वाला एक इंश्योरेंस प्लान है, जिसे खासीतर प्रभाव उपलब्ध कराता है।

प्रोफेशनल्स और बिजिनेस करने वालों उद्दिष्टियों के लिए नैयाय किया गया है।

कोटक महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ महेश बालासुभ्रामण्यम ने कहा कि कोटक लाइफ में हायार हमेशा से यह प्रयास रहा है कि हम ऐसे समाधान प्रदान करें जो प्राप्तिकार होने के साथ साथ भवित्व की दृष्टि से भी उपयुक्त हों। कोटक सिनेमर टर्म प्लान भारत के बढ़ते समृद्ध प्रोफेशनल्स और उद्दिष्टियों के लिए एक सोन-समझकर तैयार किया गया समाधान है।

छात्रवृत्ति कार्यक्रम घोषित

नई दिल्ली। एजुकेशन कंपनी

फिजिक्सवाला (पीडब्ल्यू) ने नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट 2025

के द्वारा संस्करण की घोषणा कर दी

है। यह स्कॉलरशिप के लिए संस्करणों के लिए नैयाय किया गया है।

फिजिक्सवाला नेशनल स्कॉलरशिप

कम एडमिशन टेस्ट 2025 के ज़रिए

हम इसे बढ़ावाना चाहते हैं। हर बच्चे को

समान अवसर मिलना चाहिए।

इस इनिशिएटिव के माध्यम से हम हर बच्चे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।

ऑनलाइन मोड के लिए छात्र 1 अक्टूबर

से 15 अक्टूबर के बीच परीक्षा दे सकते हैं। ऑफलाइन मोड में परीक्षा 5

अक्टूबर और 12 अक्टूबर को होगी।

स्थानीय निकायों को मजबूत करने पर ध्यान दे वित्त आयोग : राजन

नई दिल्ली (भाषा)

भारतीय रिजिट बैंक (आईआई) के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि 16वें वित्त आयोग को स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं और पंचायतों के अधिक धनराशि आवंटित करने पर ध्यान देने की जरूरत है। धनराशि का यह तीसरा स्तर होगा जिसकी हमें काफ़ी आवश्यकता है। चीन और अमेरिका का उदाहरण देते हुए राजन ने कहा कि इन देशों में स्थानीय सरकारों की कर्मचारियों की संख्या भारत में स्थानीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या से काफ़ी अधिक है।

राजन ने एक बात चीज़ में बीमा को अधिक धनराशि हस्तांतरित

की थी। उन्होंने कहा, 'अब हमें राज्यों से नार पालिकाओं और पंचायतों आदि को धनराशि हस्तांतरित करने के लिए भी ध्यान देने की जरूरत है।' धनराशि का यह तीसरा स्तर होगा जिसकी हमें काफ़ी आवश्यकता है। चीन और अमेरिका का उदाहरण देते हुए राजन ने कहा कि इन देशों में स्थानीय सरकारी कर्मचारियों की संख्या से काफ़ी अधिक है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत जैसे विशाल देश में,

जिसका शासन मुख्यतः केंद्र और राज्य की राजधानियों से संचालित होता है वहाँ अधिक विकेन्ट्रीकरण की आवश्यकता है।

'विकेन्ट्रीकरण' से तात्पर्य लेने की शक्ति और प्रशासनिक जिमिटेशनों को केंद्र सरकार से लेकर नियन्त्रण स्तरों तक, जैसे



राजन ने कहा, 'मेरा माना है कि 16वें वित्त आयोग को प्रलोग और दंड के माध्यम से इसे संभव बनाने पर ध्यान देना चाहिए।' हाल ही में 16वें वित्त आयोग के लिए भारत सरकार ने कहा था कि वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पन्हाड़ा ने कहा था कि अधिकारी ने सिफारिश की

है कि केंद्र को कर राजस्व विवरण में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाकर देनी चाहिए।

राज्यों को वर्तमान में विभाज्य कर पाल वर्ष 2024 प्रतिशत विवरण की विवरण में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाकर देना चाहिए। भारतीय संविधान द्वारा अधिकारी ने कहा है कि सभी सरकारी कार्यालयों की तरह इसमें भी कुछ सफलता मिला। यह विवरण में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाकर देना चाहिए।

तथा राजकोषीय हस्तांतरण के विभान पहलुओं पर ध्यान सरकारों को सिफारिशें भेजता है।

उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के बारे में उनका आकलन पछ जाने पर, राजन ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि हमारे पास पोलिआर्ट योजना का मूल्यांकन करने के लिए कोई ठोका सरकारी कार्यालयों की तरह इसमें भी कुछ सफलता मिला। यह विवरण में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाकर देना चाहिए।'

उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों की तरह इसमें भी कुछ सफलता मिला। यह विवरण में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाकर देना चाहिए।

नई दिल्ली (एजेंसियां)

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और एशियार्स कमज़ोर निवेश वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने मध्य-वर्षीय अधिक परिदृश्य में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घेरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत के अनुमान को घटा दिया है।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने मध्य-वर्षीय अधिक परिदृश्य में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घेरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत के अनुमान को घटा दिया है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घेरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत के अनुमान को घटा दिया है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घेरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत के अनुमान को घटा दिया है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की सकल घेरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत के अनुमान को घटा दिया है।

